



मंगलवार, 24 सितंबर 2024, लखनऊ M sattasanket@gmail.com

R.N.I. No.: UPHIN/2016/69492

वर्ष 09, अंक 112 04 पेज, मूल्य ₹1.00

सुलतानपुर की सराफा डैकेती में फरार अनुज सिंह मुठभेड़ में ढेर



उनाव, संवाददाता।

उत्तर प्रदेश में उनाव जिले के अचलगंज क्षेत्र में पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने सोमवार को एक सशस्त्र मुठभेड़ में सुलतानपुर में सराफा लूट काड़ में एक लाख रुपये ■ शेष पेज 04 पर

मुठभेड़ में मारा गया ठाकुर

अमेठी, संवाददाता।

सुलतानपुर सराफा लूट काड़ के आरोप में पुलिस ने एकांटर्टमेंट पर अनुज प्रताप सिंह के पिता ने सरकार व सपा मुख्यमंत्री पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। मोहनराज के जनापुर में सरकारी सिंह ने कहा कि उनका



मार दिया है तो कहाँ किसे कहा कि जिन लोगों पर 35 से 40 मुकदमे हैं। उनका कुछ नहीं हो रहा है। उनके बेटे पर एक मुकदमा था और सुलतानपुर डैकेती में नाम आया। पुलिस ने उनके ■ शेष पेज 04 पर

बसों का फास्ट टैग हैक
युकाना पड़ा दो गुना टोल
लखनऊ, संवाददाता।

परिवहन नियम की 20 बसों के फास्ट टैग हैक होने की सूचना से सोमवार को विधाया में हड्डम मच गया। टोल प्लाजा पर इन बसों के फास्ट टैग के बॉक्स बता दिया गया। कई पर टोल कर्मसुगी ने कहा कि यह एसटीएफ से जुड़ा है तो कहाँ दुसरे बैंक का बताया गया जबकि इन बसों के टैग एसटीएफ के सरकारी बैंक खाते से समझदाहूँ हैं। बैंकों बताये की बजाए इन बसों से इनका सुचना पर अक्सरों ने देटेक्ट बैंक को देने के साथ ही साइबर थाने में भी शिकायत की है। अक्सरों ने आशंका खाते कि किंहीं साइबर अपराधी इन हक्रकत के जरिये सरकारी खाते से बड़ी धनराशि उड़ाने का प्रयास तो नहीं कर रहे थे।

सुलतानपुर डैकेती प्रकरण- अखिलेश यादव ने कहा

फर्जी एनकाउंटर नाइंसाफी है

लखनऊ, एजेंसी।

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सुलतानपुर डैकेती केस में यूपी एसटीएफ की कार्रवाई पर कहा कि सबसे कमज़ोर लोग एनकाउंटर को अपनी शक्ति मानते हैं। फिरी का भी फर्जी एनकाउंटर नाइंसाफी है।



वो जाते-जाते उत्तर प्रदेश में ऐसे हालात पैदा कर देना चाहते हैं कि वहाँ कोई नियंत्रण ही ना चरे। उत्तर प्रदेश की जागरूक जनता ने जिस तरह लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराया है, भाजपा उसी का बदला ले रहे हैं। अंत में समाजवादी प्रक्रिया के प्रमुख ने एनकाउंटर के निवारण बताते हुए कहा जिनका खुला का कांव भविष्य नहीं होता, वही लोग दूसरों का भविष्य बिगड़ते हैं। जब अखिलेश यादव ने उनाव में हुए एनकाउंटर में डैकेती के आरोपी अनुज सिंह के मारे जाने पर एक बड़ा चुप्पा आया। एनकाउंटर कर ■ शेष पेज 04 पर

खास खबर

82 बीईओ पर कार्रवाई की तैयारी

लखनऊ। शिक्षकों के बेतन बढ़ि को रोकने वाले 82 बीईओ पर नियंत्रण की तरफार लकड़ गई है। जास्ती ने ऐसे सभी बीईओ (खण्ड शिक्षा अधिकारी) के खिलाफ द्वारा उनाव में एसटीएफ के आरोपी ने दूरीजाले के बीच साथी भर्तीयों की ताकि जिले में स्थानीय बोर्ड पर 2700 शिक्षकों की बेतन बढ़ि सभी मामले की ओर तक लकड़ का स्वरूप है। दरवाजल विधाया परिषद में शिक्षक दल के नेता ध्वनि कुमार त्रिपाती ने इस मामले को मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाते हुए तलाव शिक्षकों के बेतन बढ़ि के अदेश यादव करने की मांग की थी। मुख्यमंत्री सचिवालय ने मामले को गमीनीया से लेते हुए तलाव अधितन जानकारी दी।

कई विभागों में कार्योजना लागू नहीं
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी अदित्यनाथ द्वारा करोड़ लाख साल पहले दी गई कार्योजना पर अमल करने को ज्यादातर विभागों को कार्रवाई दिया गई है। एक बीच 30 विभागों ने अपना काम राहीं तरीके से किया है। 64 विभागों ने आधा अंडरूर फोरेकेक दिया है। अब योगी सरकार ने इन्हीं 64 विभागों के अपर मुख्य सचिवों को प्रधानमंत्री के बाप भर्ती कर अधूरे काम की ओर बढ़ा दिया है। इसमें कहा गया है कि सीएएआईएस (मुख्यमंत्री अनुवरण प्रणाली) पोर्टल पर 6 माह, एक वर्ष, दो वर्षों की आयोजना व उस पर अमल शिर्षों पर प्रवेषक माह की 5 तरीकों तक देनी थी लेकिन पोर्टल पर उनको प्रयाप्त आडेट नहीं हो रही है। कार्रवाई क्रियान्वयन विभाग ने नामी विभागों को प्रभं भेजा गया है। 17 मई 2022 के आदेश की ओर दिया है। इसमें कहा गया है कि विभागों की अपनी कार्योजना सीएएआईएस पोर्टल पर अपलोड करनी थी जो अपने तक नहीं हुई।

बसों का फास्ट टैग हैक
युकाना पड़ा दो गुना टोल
लखनऊ। परिवहन नियम की 20 बसों के फास्ट टैग हैक होने की सूचना से सोमवार को विधाया में हड्डम मच गया। टोल प्लाजा पर इन बसों के बॉक्स बता दिया गया। कहीं पर टोल कर्मसुगी के बैंकों ने कहा कि यह एसटीएफ से जुड़ा है तो कहाँ दुसरे बैंक का बताया गया जबकि इन बसों के टैग एसटीएफ के सरकारी बैंक खाते से समझदाहूँ हैं। बैंकों बताये की बजाए इन बसों से इनका सुचना पर अक्सरों ने देटेक्ट बैंक को देने के साथ ही साइबर थाने में भी शिकायत की है। अक्सरों ने आशंका खाते कि किंहीं साइबर अपराधी इन हक्रकत के जरिये सरकारी खाते से बड़ी धनराशि उड़ाने का प्रयास तो नहीं कर रहे थे।

बसों का फास्ट टैग हैक
युकाना पड़ा दो गुना टोल
लखनऊ। परिवहन नियम की 20 बसों के फास्ट टैग हैक होने की सूचना से सोमवार को विधाया में हड्डम मच गया। टोल प्लाजा पर इन बसों के बॉक्स बता दिया गया। कहीं पर टोल कर्मसुगी के बैंकों ने कहा कि यह एसटीएफ से जुड़ा है तो कहाँ दुसरे बैंक का बताया गया है। अब योगी सरकार ने इन्हीं 64 विभागों के अपर मुख्य सचिवों को प्रधानमंत्री के बाप भर्ती कर अधूरे काम की ओर बढ़ा दिया है। इसमें कहा गया है कि सीएएआईएस (मुख्यमंत्री अनुवरण प्रणाली) पोर्टल पर 6 माह, एक वर्ष, दो वर्षों की आयोजना व उस पर अमल शिर्षों पर प्रवेषक माह की 5 तरीकों तक देनी थी लेकिन पोर्टल पर उनको प्रयाप्त आडेट नहीं हो रही है। कार्रवाई क्रियान्वयन विभाग ने नामी विभागों को प्रभं भेजा गया है। 17 मई 2022 के आदेश की ओर दिया है। इसमें कहा गया है कि विभागों की अपनी कार्योजना सीएएआईएस पोर्टल पर अपलोड करनी थी जो अपने तक नहीं हुई।

हम बंटे थे तो कटे थे

इसलिए 500 वर्ष तक अयोध्या में इंतजार करना पड़ा: मुख्यमंत्री योगी

मिजारू, एजेंसी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या में प्रथम रामलला के भव्य मंदिर को तोड़कर आक्रान्तों ने गुलामी का ढांचा खड़ा कर दिया था। उसका कारण एक ही है, हम बंटे थे, इसलिए एक बालि भी, बल्कि एक जुटे होने के बालि भी तोड़ते हैं।



सीएम योगी ने नवरात्रि को मिशन शक्ति अभियान को समर्पित करने के लिए दिये हैं निर्देश

लखनऊ, एजेंसी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर संस्कृति विभाग आगामी नवरात्रि पर भव्य आयोजन में जुट गया है। प्रदेशभर के सभी देवी मंदिरों और शक्तिपीठों में विविध संस्कृति करना लाभी है।

जिला, तहसील और ब्लॉक स्तर पर गठित होगी समिति

चाइल्ड पोर्न देखना अपराध

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, डाउनलोड करना भी क्राइम की श्रेणी में

नवी दिल्ली, एजेंसी।

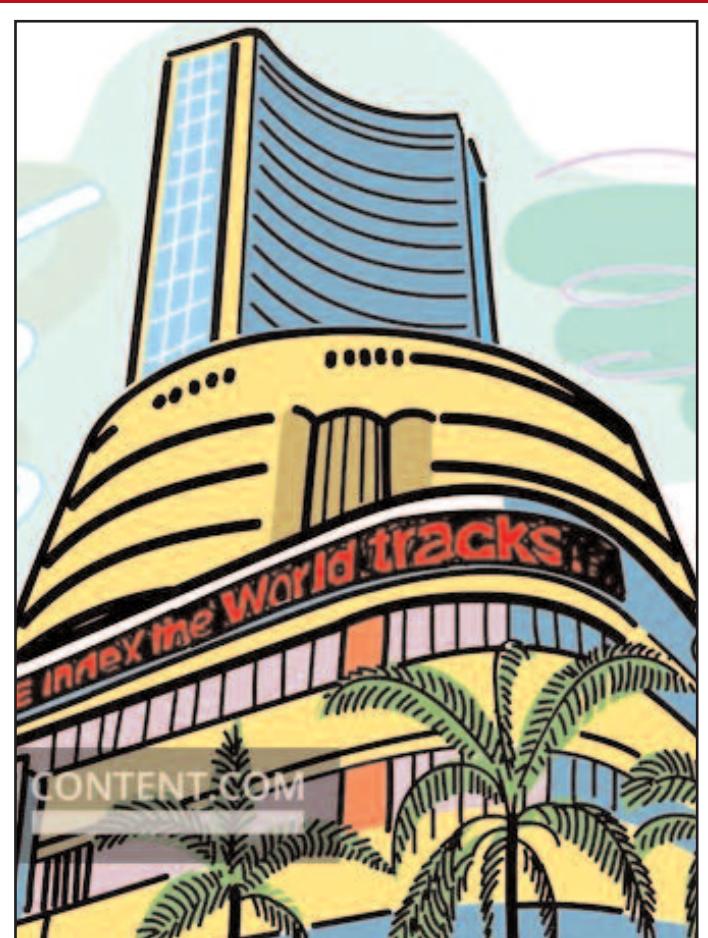
उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को अपने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा कि बच्चों के साथ यौन-क्रिया के स्पष्ट चिह्न और उनसे संबंधित अपराधों को समझदाहूँ हैं। अब योगी सरकार ने स्टेट एक्ट के बालि भी बैंक में आयोजित विभागों के बीच संगठन जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन अलायंस की अपील और राष्ट्रीय बाल अधिकारी सरकारण आयोजन के हस्तक्षेप पर इस विषय के दृष्टिकोण से बालि भी बैंक के बच्चों के संशोधन लाने पर गंभीरा से विचार करना चाहिए। योगी ने यह भी कहा कि इस संशोधन के लिए फिलाहाल सरकार आयोजन आयोजन की ओर बढ़ावा देना चाहिए। योगी ने कहा कि बच्चों के साथ यौन-क्रिया के स्पष्ट चिह्न और उनसे संबंधित अपराधनक असमानों को रखना चाहिए। योगी ने कहा कि बच्चों के साथ यौन-क्रिया के स्पष्ट चिह्न और उनसे संबंधित अपराधनक असमानों को रखना चाहिए। योगी ने कहा कि बच्चों के साथ यौन-क्रिया के स्पष्ट चिह्न और उनसे संबंधित अपराधनक असमानों को रखना चाहिए। योगी

सम्पादकीय

अभिव्यवित की आजादी के लिए जरूरी फैसला

बॉन्डे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की देखा करते हुए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने केंद्र सरकार की तरफ से पिछले साल लाए गए इफॉर्मेशन टेक्नालॉजी संशोधित नियम- 2023 में किए गए फैक्ट चेक यूनिट गठन के प्रावधान को नियन्त्रण कर दिया है। इस फैसले को सुनाने हुए जस्टिस अनुल चंद्रसुक्त ने माना कि एफसीयू संविधान के अनुच्छेद-14 (समाजता का अधिकार), 19 (बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी), 191-जी (पेशे के अधिकार) और 21 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। आईटी नियमों ने फॉर्मूला कामक और झूठ जैसे शब्दों की व्याप्ति पूरी तरह से अव्याप्त है, जो तारिकता की कस्तूरी पर स्थायी नहीं उत्तरी है। दस्तावेज केंद्र सरकार ने सोशल नीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, टिकटक, यूट्यूब आदि पर फॉर्मूला कामक और झूठी घबराई पर शिकंजा करने के उद्देश्य से फैक्ट चेक यूनिट की व्यवस्था बनाई थी, ताकि सरकार के कामकाज की सही और सटीक सूचनाएं नागरिकों तक पहुंचे। इस व्यवस्था में यदि सोशल नीडिया ने कोई झूठी घबराई डाली जाती है, तो एफसीयू उसे चिन्हित करेगा, फिर उसे वहां से हटाया जाएगा। लेकिन चर्चित स्टैंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा समेत कुछ और याचिकाकाताओं ने इस प्रावधान के दिवालाफ बॉन्डे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

उनका कहना था कि पे स्पृष्टिन अभिव्यक्ति और विचारों की स्थतंत्रता पर अनुचित प्रतिवंश लगा देगा। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इन प्रावधानों से ऑनलाइन कंटेंट पर स्टेट्यूटिशन लग जाएगी। स्टेट्यूटिशन को इस बात का 'अभियोजक, जज़ बनने का औका निल जाएगा कि ऑनलाइन क्या 'स्टेट्यूटिशन' किया जाएगा इस याचिका पर जनवरी, 2024 में हाई कोर्ट की जटिल पटेल और जटिल नीला गोखले की बेंच ने विभाजित फैसला सुनाया था। जटिल पटेल के नुताबिक, एफसीयू ऑनलाइन सूचनाओं पर एक स्टेट्यूटिशन का काम करेगा। वहीं जटिल गोखले के अनुसार, एफसीयू दुर्भावना से भयी सूचनाओं को फैलने से दोकेगा। केवल एफसीयू के दुरुपयोग की संभावना के आधार पर इसे अमान्य नहीं किया जा सकता है। हाईकोर्ट का फैसला आने के इंतजार में फैक्ट-चेक यूनिट संचालित करने के नोटिफिकेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मार्ग में स्टे लगा दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केंद्र इस नामले में तब तक आगे नहीं बढ़ सकता, जब तक बॉम्बे हाई कोर्ट इसकी संवैधानिक वैधता पर निर्णय नहीं लेता है। दो जजों की नामिन्नता को देखते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जटिल डी.के.उपाध्याय ने केस को तीसरे जज चांदूरकर के पास भेजा था। जिन्होंने शुक्रवार को यह माना है कि एफसीयू की व्यवस्था असंवैधानिक है इस फैसले को इस नजरिए से ऐतिहासिक कहा जा सकता है कि इससे एक तरफ अभिव्यक्ति के अधिकार की दृश्य हुई है, दूसरी तरफ संविधान प्रदत्त अधिकारों पर परोक्ष तरीके से एक लगाने की कोशिश को दृष्टि किया गया है। केंद्र स्टेट्यूटिशन के इसादे माले दुर्भावनापूर्ण सूचनाओं के प्रत्यारोपण को दोकने के छठे हों, लेकिन जिस तरह से अंकुश लगाने की कोशिश स्टेट्यूटिशन कर दी थी, उसमें यह आशंका लगातार बनी दृष्टि कि दुर्भावना का पैमाना स्टेट्यूटिशन की सुविधा के नुताबिक ही तय किया जाता। गोदी स्टेट्यूटिशन के कार्यकाल की शुरूआत से ही नीडिया के एक बड़े तबके पर किया तरह पूँजीपतियों और स्टेट्यूटिशन तंत्र का शिकंजा करना जा चुका है, यह अब उद्घाटित सत्य है। दूरदर्शन तो पूरी तरह पक्षपाती द्वया प्रदर्शित करता है, इसके साथ-साथ निजी चैनल भी निष्पक्षता का लगाना कर चके हैं।



19 सितंबर दुनिया भर के वित्तीय बाजारों के लिए एक बड़ा दिन था। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने आखिरकार वैसा ही किया जैसा बाजारों को उम्मीद थी। इसने ब्याज दरों में भारी कटौती की। इसका वैश्विक स्तर पर व्यापक असर हो रहा है और शेयर बाजारों, जो पहले से ही समायोजन कर रहे हैं, को अधिक समायोजन करना पड़ रहा है, जैसा कि हमने भारतीय बाजार में तेज उछाल के दौरान देखा है। मार्च 2020 के बाद से अमेरिकी केंद्रीय बैंक की ओर से यह पहली ब्याज दर कटौती है सबसे अधिक ध्यान देने वाली बात यह है कि अमेरिकी फेड ने सभी उम्मीदों को पार कर लिया है और पहले से कहीं अधिक कटौती की है - जैसा कि कुछ टिप्पणीकारों ने इसे 'आधा प्रतिशत की भारी कटौती' कहा है। इसके परिणाम स्वरूप शेयर बाजार आश्वर्यचिकित दंग से ऊपर की ओर जा रहे हैं। कुछ टिप्पणीकार मौद्रिक नीति निर्माण के इस बड़े कदम को 'फ्रॅंट लोडिंग' के रूप में वर्णित कर रहे हैं ऐसा करते हुए, फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोमपॉवेल ने कहा कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था मजबूत और स्वस्थ है, और लगातार बढ़ रही है।

साथ ही, ब्याज दरों को ऐतिहासिक उच्च स्तर पर रखने के बावजूद, अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है और मंदी में नहीं फंसी है साथ ही, कीमतों में तेजी से गिरावट आई है और मूल्य मुद्रास्फीति लगभग लक्ष्य स्तर के भीतर है। उन्हें लगा कि मुद्रास्फीति को नियन्त्रित करने की लड़ाई जीत ली गई है और इसलिए उन्होंने अपनी नीति ब्याज दर में आधे प्रतिशत की कटौती की, भले ही इसके बारह गवर्नरों में से एक इस धारणा से अलग थे और एक चौथाई प्रतिशत की कम कटौती की वकालत की इसका निश्चित रूप से वैश्विक स्तर पर प्रभाव पड़ेगा। प्रमुख देशों के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के कदम के जवाब में अपनी ब्याज दरों को फिर से निर्धारित कर सकते हैं। हर तरफ दरों में कटौती की उम्मीद की जा सकती है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के फैसले से वैश्विक स्तर पर धन के प्रवाह हर असर पड़ेगा। यह उम्मीद करना उचित है कि उभरते बाजारों की अर्थव्यवस्थाओं का लाभ उठाने के लिए फंड मैनेजर इन बाजारों में कुछ अतिरिक्त निवेश करेंगे। भारतीय शेयर बाजार प्रमुख संस्थागत निवेशकों के लिए एक लक्ष्य है और सबसे प्रमुख वैश्विक शेयर सूचकांकों में से एक में भारत का महत्व चीन के मुकाबले मामूली रूप से बढ़ा है। भारतीय शेयर बाजार में पहले से ही तेजी देखी जा रही

ज्योति बसु भी
चले गए, सोमनाथ
चटर्जी भी और
सीताराम येचुरी
भी। मगर जैसा
सीपीआईएम ने
1996 में ज्योति
बसु को प्रधानमंत्री
नहीं बनाने के
लिए तर्क दिया था
कि हमारे पूर्ण
बहुमत होने तक
हम अपने सिद्धांत
लागू नहीं कर
सकेंगे इसलिए उस
सरकार में जहां
हमारे सदस्य कम
हैं हम प्रधानमंत्री
नहीं बना सकते।
ज्योति बसु नहीं
बने और आज 28
साल हो गए लेफ्ट
खासतौर से
सीपीआईएम और
कमज़ोर हुआ है।

ओडिया की घटना से सेना में योष

विषयातंर हो रहा है लेवि और मूलरूप से तो विषय एक पुराने विषय की कताकि आज की परिस्थिति समझ में आ सकें। राजनीति किसी सिद्धांत में फिर राजनीति के बदलते रूप और उन्हें सुधारते हैं बासे की थी कि उस समय नए नए बने महासंचिव कहा था- यह फासिज्म नहीं है। अब पूरा हुआ कि शायद बताया नहीं या बताया हमने कहा कि बापार्टी, किसी ने सुना अखबारों में अब रिपोर्ट है हमने बात शुरू की इन्स्टिट्यूशन के रूप में रख उसी संदर्भ में यह आया 2014 से ही कर दी थी। समझ में नहीं आया वह मगर जो जानते थे उनकी अकादमिक बहसों में लोबड़ा नुकसान किया। इन्स्टिट्यूशन के प्रधानमंत्री आया। जो वास्तव में साबित हुई। और यह आखिरी नहीं थी। ऐसे ही अड़ना। यूपीए सरकार ने लेना। सोमनाथ चटर्जी अध्यक्ष थे उनके खिलाफ कार्रवाई करना। दस बारों को पार्टी से ही निकाला 2008 में यूपीए से समर्थन सीपीआईएम ने चटर्जी अध्यक्ष पद छोड़ने को बोला। तो उन्हें पार्टी से बांद गया।

कई बार लगता है कि यह जैसा है। जैसे वे कब बनाकर अड़ जाते हैं वैसे नियम बचे रह गए व्यक्ति देश भर में सीपीआईएम सीताराम येचुरी की याद है। आम लोग बड़ी तादाद हैं। और बहुत दिल से नियम कर रहे हैं। हमने उनकी मठ डेढ़ महीने पहले उनके मुलाकात में कहा था राजकीय बहुत खलती है।

लास्ट इंस्टिट्यूशन था सेना !
उसे भी खत्म कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अभी ओडिशा पुलिस थाने में महिला यौन उत्पीड़न की भयावह घटना के बाद अचानक यह हुआ हो।

हो तो पहले से रहा है मगर किसी दूसरी फोर्स को उसके खिलाफ ऐसा विवाद खड़ा नहीं किया गया था। अब सेना के खिलाफ बाकायदा उड़ीसा पुलिस को उतार दिया गया है सेना देश के पवित्रतम संस्थाओं में मानी जाती है। ज्यूडिशरी और सेना यह वह इन्स्टिट्यूशन हैं जो किसी बड़ी से बड़ी घरेलू विपत्ति में भी डटे रह सकते हैं। बशर्ते कि उनका राजनीतिकरण नहीं किया जाए। 2014 में नरेन्द्र मोदी जिस तरह प्रधानमंत्री बने आडवानी और मुरली मनोहर जोशी जैसे अपने सबसे बड़े नेताओं को धकेल कर रास्ते से हटाया उससे यह आभास हो गया था कि मोदी गुजरात की तरह यहां भी तानाशाही करेंगे। मगर हमारे यहां बुद्धिजीवी ऐसे हैं कि वे

इसमें तानाशाही की फासिज्म की परिभाषा एं रखकर नापतौल कर रहे थे कि यह फासिज्म है या अर्द्ध फासिज्म? इसके इटली के स्वरूप और जर्मनी के रूप में क्या फर्क था। खैर वह सिद्धांतकारी खुद उनकी पार्टी में फेल हो गए, मगर वे सिद्धांत बड़ा है व्यवहारिक जरूरतों से इस पर अड़ रहे और आज केवल सिद्धांत है, किस पर लागू किया जाए वह कोई बचा ही नहीं है। ज्योति बसु भी चले गए, सोमनाथ चटर्जी भी और सीताराम येचुरी भी। मगर जैसा सीपीआईएम ने 1996 में ज्योति बसु को प्रधानमंत्री नहीं बनाने के लिए तर्क दिया था कि हमारे पूर्ण बहुमत होने तक हम अपने सिद्धांत लागू नहीं कर सकेंगे इसलिए उस सरकार में जहां हमारे सदस्य कम हैं हम प्रधानमंत्री नहीं बना सकते। ज्योति बसु नहीं बने और आज 28 साल हो गए लेपट खासतौर से सीपीआईएम और कमजोर हुआ है। इतना कि लाल किले से लाल सलाम का नारा अब लगाया भी नहीं जाता।

जह जरूरी है। उन्होंने जो ज़ोड़ना है, सही तरीके से एक घटनाक्रम नहीं होता है। सिद्धांत बनाते हुए उन्होंने फासिज्म औपीआईएम के नाश करात ने अर्द्ध फासिज्म नहीं। यह उन्होंने भी होगा तो नोर हो गई है। नहीं होगा। भी नहीं होता सेना के भी नहीं करने की तो कि शुरूआत वह जिनकी अलग बात है। अनावश्यक को उलझाकर सिलसिले में नाना का जिक्र गहासिक भूल अंकली या यूक डील पर समर्थन वापस नो लोकसभा नुशासनात्मक सांसद चटर्जी दिया गया था। वापसी के बाद से लोकसभा। उन्होंने नहीं निकाल दिया अच्छों के खेल में कोई नियम ही यहां सिर्फ गण गण इन दिनों के महासचिव सभाएं हो रही उनमें आ रहे गाराम को याद से करीब एक साथ अखिरी भा में आपकी लाकात संसद भवन में ही हुई थी। एनेक्सी के मेडिकल सेंटर में। तबीयत तो खराब चल ही रही थी। बोले भी कि बुढ़ापा! हमने विरोध किया। बात को बदलने के लिए उनके राज्यसभा के उस ऐतिहासिक दिन की याद दिलाई जिस दिन उन्होंने सदन में सभापति को मत विभाजन के लिए मजबूर करके मोदी सरकार को हरा दिया था। फिर ऐसा कोई नहीं कर पाया। खुशी छलकी चेहरे पर। मुस्कराते तो वे हमेशा रहते थे। मगर अंदर की खुशी उस समय बाहर आई। थोड़ी बातें हुईं। और हमने कहा कि आपकी पार्टी का और आप खुद महासचिव थे आपका गलत फैसला कि आपकी राज्यसभा कंठीन्यु नहीं की गई। हंसते रहे। हमने कहा इंटरव्यू करें। कहने लगे आ जाइए। मगर वह मौका ही नहीं आया तो यह एक और बड़ी भूल थी सीपीआईएम की कि राज्यसभा में उसने अपने सारे अच्छे स्पीकरों को हटा लिया। इस नियम के चलते कि दो बार से ज्यादा किसी को राज्यसभा नहीं मिलेगी। लोकसभा का टिकट कितनी बार भी मिल जाए। मुख्यमंत्री कितने साल भी रह ले। राज्यसभा नहीं देंगे! तो राज्यसभा जहां एक अकेले सीताराम ने दस साल केवल लेफ्ट की आवाज ही बुलंद नहीं रखी सदन में चचाओं के स्तर को एक नई ऊँचाइयों तक पहुंचाया। खैर बात कहां से कहां पहुंची। मगर ठीक है। मोदी से जिक्र शुरू हुआ था किस तरह उन्होंने देश के सारे इन्स्टट्यूशन को खत्म कर दिया। मीडिया का तो जिक्र ही क्या? उसकी तो बात करने लायक भी स्थिति नहीं बची है। बाकी भी सारे संस्थानों की स्वायत्ता खत्म कर दी गई है। न्यायालिका कभी-कभी आभास देती है कि वह कुछ कर रही है। कर सकती है। मगर उस पर दबाव लगातार बढ़ाया जा रहा है कि वह भी पूर्ण समर्पण कर दे। कभी व्यंग्य करके। चुनावी बांड के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद खुद प्रधानमंत्री ने उस पर कृष्ण और सुदामा की कहानी के माध्यम से चोट करने की कोशिश की थी। और अभी तो चीफ जस्टिस चन्द्रचूड़ के घर का वीडियो रिलीज करके। चीफ जस्टिस अभी तक जवाब नहीं दे पाए। सेना के मामले में भी जब बिपिन रावत की सीडीएस बनाया था तो उनके बयानों ने बताया कि कैसे वे सेना के राजनीति से दूर रहने के पवित्र सिद्धांत की अवमानना कर रहे हैं। सीताराम येचुरी की बात हुई है तो याद आता है रावत के बयानों पर उन्होंने चेताया था कि सेना के इस तरह के हस्तक्षेप हमें कहीं पाकिस्तान के रास्ते पर न ले जाएं रावत ने असम के मामले में एकदम खुलकर राजनीतिक बात की थी। बदरदीन अजमल की पार्टी और जनसंघ की विवादास्पद तुलना की थी। इसी तरह कश्मीर पर, स्टूडेन्ट पर, नागरिकता संशोधन कानून पर उनके कई बयान हैं जो इससे पहले कभी सोचे भी नहीं जा सकते थे कि कोई सेना का अधिकारी कभी ऐसा भी बोल सकता है इससे सेना का दर्जा गिरा। उसकी जो अपना अलग एक पहचान थी वह कमजोर हुई सेना को भी दूसरी फोर्सों की तरह लिया जाने लगा। मध्यप्रदेश के महू में जो सैन्य छावनी है। थोड़ा पत्रकारों का भी उससे संबंध है। वहां पत्रकारों को बार करस्पान्डेट की ट्रेनिंग दी जाती है। वहां दो आर्मी ऑफिसर और उनकी महिला मित्रों के साथ मारपीट की गई। फिरौती मांगी गई। रेप किया गया। कभी सुना था ऐसा? आर्मी इलाकों के पास गुंडे बदमाश फटकते नहीं थे। आसपास के बाजारों में महिलाएं देर रात तक अकेली शारिंग करती थीं। और अब महू की घटना के बाद पता है मीडिया ने क्या सवाल उठाए? देर रात महिलाएं घर से बाहर क्यों निकल रही हैं? उनके पुरुष मित्रों के साथ घूमने का औचित्य? महिला और सेना पर ऐसे ही सवाल अब ऑडिशा की पुलिस उठा रही है। सेना के युवा अफसरों में बहुत रोष है। सेन्ट्रल कमान ने टर्वीट करके कहा है कि हम ऑडिशा के मामले को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। पूर्व सेना अधिकारियों ने वहां सड़कों पर प्रदर्शन किया। थाने के अंदर सेना के अधिकारी जो शिकायत लेकर आए हैं उनके साथ मारपीट और मंगेतर के कपड़े उतार कर रेप की धमकी कभी नहीं सुना था। और सबसे खराब बात की प्रधानमंत्री मोदी चुप हैं। खाली बगाल पर बोलते हैं। हालांकि बगाल में कोई आरोपी के साथ नहीं आया। लेकिन जहां भी बीजेपी की सरकार है मणिपुर से लेकर अभी ऑडिशा तक वहां सबसे पहले आरोपियों को समर्थन मिलता है। पीड़िता परिवार पर सवाल उठाए जाते हैं। देश को बहुत खतरनाक स्थिति में पहुंचा दिया गया है। पुलिस उल्टे सेना पर आरोप लगा रही है।

पत्रकारिता एवं दाष्टवादी सोच के जुङ्गाएँ-व्यक्तित्व



-प्रो. महेश चौध

पत्रकारिता एवं समाजसेवा के एक जुङ्गारू

वैचारिक क्रांति के सूत्रधार, उत्कृष्ट राष्ट्रवादी एवं अनेक पत्रिकाओं के सम्पादक ललित गर्ग का जीवन एक संभावनाओं भरी प्रेरक जीवन की दास्तान है। उनका जीवन सफर आदर्शों एवं मूल्यों की पत्रकारिता की ऊँची मीनार हैं। वे पत्रकार, लेखक, स्तंभकार हैं, वही उनका सामाजिक जीवन भी प्रेरक हैं। उन्हें निर्भीक विचारों, स्वतंत्र लेखनी और बेबाक राजनैतिक टिप्पणियों के लिये जाना जाता रहा है। उनको पढ़ने वाले लोगों की संख्या लाखों में है और अपने निर्भीक लेखन से वे काफी लोगों के चहेते हैं। वे न केवल अपने वैचारिक आलेखों के जरिये राष्ट्र की ज्वलंत समस्याओं को सशक्त तरीके से पीड़ितों और मजलूमों की आवाज बनते रहे। अपनी कलम के जरिये उन्होंने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी कलम जब भी चली उन्होंने लाखों लोगों की समस्याओं को सरकारों और प्रशासन के सामने रखा और भारतीय लोकतंत्र में लोगों की आस्था को और मजबूत बनाने में योगदान दिया। ललित गर्ग को हम भारतीयता, पत्रकारिता एवं सामाजिकता का अक्षयकोष कह सकते हैं, वे चित्रता में मित्रता के प्रतीक हैं तो गहन मानवीय चेतना के चित्रे जुझार, निडर, साहसिक एवं प्रखर व्यक्तित्व हैं। लाखों-लाखों की भीड़ में कोई-कोई ललितजी जैसा विकास की प्रयोगशाला प्रशिक्षणों-परीक्षणों से गुमौलिक सोच, कर्मठता, कुरुर्थान एवं भावनाएं-परीक्षणों से गुमौलिक सोच, कर्मठता, कुरुर्थान को अभिप्रेरित करता है। उन्होंने संतुलित समाज निर्माण के अभिनव दृष्टिकोण, सामाजिक इरादों की शुरूआत एवं ऐसे जीवन की दास्तान जीवन को बिन्दु से सिद्ध्युत जीवन की दास्तान को पद बारे में एक नई सोच पैदा करना सोचने, पत्रकारिता एवं सामाजिक आलेखों के जरिये राष्ट्र की ज्वलंत समस्याओं को सशक्त तरीके से

में विभिन्न कर अपनी जिजीविषा, आमाज एवं राष्ट्र में आदर्श एवं लिखित कई नए क सोच और की। ललितजी जिन्होंने अपने पाया है। उनके हुए जीवन के दोती है। उनके कुछ मौलिक नक जीवन को सद्गृहितियों को जागृत करने की प्रेरणा मिलती रहेगी।

ललित गर्ग एक सरल सा व्यक्तित्व। हर किसी के सुख दुख में साथ खड़े रहने वाले समाजसेवी ललित गर्ग का जन्म 24 सितंबर 1964 को राजस्थान में अजमेर जिले के किशनगढ़ में हुआ। आपको साहित्य और पत्रकारिता के संस्कार अपने पिता श्री रामस्वरूप गर्ग से मिले और समाजसेवा का हुनर अपनी दोनों माताओं स्वर्गीय श्रीमती सत्यधामा गर्ग और श्रीमती चंद्रप्रभा देवी गर्ग से विरासत में पाया। गांधी, बिनोबा और जयप्रकाश नारायण के अनन्य सहयोगी आपके पिताश्री स्व.

पत्रकार, समाजसेवी एवं विचारक रहे हैं, उन्होंने करीब तीस वर्षों तक जैन विश्वभारती के प्रारंभ से अपने जीवन के अंतिम समय तक प्रथम कार्यकर्ता के रूप में उल्लेखनीय सेवाएं प्रदान की। यही वजह है कि श्री ललित गर्ग का छुकाव तेरापंथ धर्मसंघ एवं अणुव्रत की प्रवृत्तियों में बचपन से ही शुरू हो गया था।

बचपन से कलम और स्थाही के प्रति आकर्षण के चलते आपने छोटी-सी अवस्था में ही लेखन प्रारंभ कर दिया। आपकी प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान के लाडनुं से और हाथर एजूकेशन चूरू जिले के सुजानगढ़ के सुजला कॉलेज से हुई, जहां से

अमेरिकी फेडरल रिजर्व की भारी कटौती का वैश्विक स्तर पर शेयर बाजारों पर असर

है। आज के कारोबार में शेयरों में तेजी आई है, जबकि ये पहले से ही उच्च स्तर पर हैं दर समायोजन की स्थिति में शेयरों और बांडों के तुलनीय मूल्य फिर से सरेखित होते हैं कोई सुरक्षित रूप से उम्मीद कर सकता है कि ब्याज दर घटेगी तथा शेयरों की कीमतें बढ़ेंगी। पोर्टफोलियो को फिर से नियरित किया जायेगा। अतिरिक्त फंडों में होने वाले उतार-चढ़ाव अगले चरण में विदेशी मुद्रा बाजार को भी हिला सकते हैं। कोई उम्मीद कर सकता है कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रूपये के लिए आसान दरें उल्लंघन सकती हैं और विदेशी संस्थागत निवेशकों से प्रवाह के अनुसार समायोजन दिखा सकते हैं। फिर, संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रीय बैंक ने इस समय इतना बड़ा कदम क्यों उठाया है। राय अलग-अलग हैं।

आंकड़ों की व्याख्याएं अलग-अलग हैं। फेडरल बैंक के चेयरमैन पॉवेल ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था में विपरीत स्थिति की ओर इशारा किया है। जबकि साल की शुरूआत में, कीमतें 4.2 प्रतिशत बढ़ रही थीं और बेरोजगारी दर 2 प्रतिशत पर थी। वर्तमान में स्थिति बिल्कुल उल्लट है। कीमतें 2 प्रतिशत बढ़ रही हैं और बेरोजगारी 4 प्रतिशत पर

अमेरिकी अर्थव्यवस्था का व्यवहार हैरान करने वाला रहा है। पारंपरिक आर्थिक तर्क के अनुसार, केंद्रीय बैंक ब्याज दरें तब बढ़ाते हैं जब कीमतें बढ़ रही होती हैं। उच्च ब्याज दर मांग को दबा देती है, निवेश को कम करती है, जिससे रोजगार में कमी आती है। इस प्रकार, रोजगार और मूल्य वृद्धि के बीच एक विशेष संबंध है।

है पॉवेल ने बताया कि बेरोजगारी और बढ़ने से पहले, केंद्रीय बैंक को बेरोजगारी को और बढ़ने से रोकने के लिए समग्र अर्थिक गतिविधि को समर्थन देने की दिशा में कदम उठाना होगा। वास्तव में, अर्थशास्त्रियों और बाजार संचालकों में से कुछ लोगों का मानना है कि फेड पहले से ही पाठे रह गया है, यानी उसने दरों में कटौती को बहुत लंबे समय तक टाल दिया है किंद्रीय बैंक ने अपनी नीतिगत दरों को ऐतिहासिक रूप से उच्च स्तर पर बनाये रखा था - सटीक रूप से 23 साल के उच्चतम स्तर पर। परिणामस्वरूप, बाजारों के साथ-साथ अर्थशास्त्रियों को भी उम्मीद थी कि फेड इस साल जनवरी में अपनी बैठक में नीतिगत दरों में कटौती करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर मौद्रिक नीति समिति की मार्च की बैठक में कटौती की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। फिर, जून में भी ऐसी ही उम्मीद थी। अब, सितंबर में ही कटौती हुई है पूरे समय, अर्थशास्त्रियों को डर था कि लगातार उच्च ब्याज दरों अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मंदी में डाल देंगी। यह डर लंबे समय से था। इकानॉमिस्ट पत्रिका ने इस बात पर आश्वर्य व्यक्त किया था कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था अभी भी बहु रुद्धी है बालाकि 2020 की पहली

किया था कि अमेरिका अर्थव्यवस्था जमा मां बढ़ रहा है, हालांकि 2020 का पहला तिमाही से व्याज दर में लगातार बढ़ातरी की जा रही थी। वास्तव में, अमेरिकी अर्थव्यवस्था का व्यवहार हैरान करने वाला रहा है। पारंपरिक आर्थिक तर्क के अनुसार, केंद्रीय बैंक व्याज दरें तब बढ़ाते हैं जब कीमतें बढ़ रही होती हैं। उच्च व्याज दर मांग को दबा देती है, निवेश को कम करती है, जिससे रोजगार में कमी आती है। इस प्रकार, रोजगार और मूल्य वृद्धि के बीच एक विशेष संबंध है लेकिन इस बार, फेड ने अपनी व्याज दरें तब बढ़ाईं जब अमेरिकी कीमतें ऐतिहासिक उच्च गति पर थीं। सभी को बेरोजगारी में वृद्धि और वास्तव में मंदी की उम्मीद थी परन्तु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और अमेरिका खुशी-खुशी बढ़ता रहा। साथ ही, हाल ही में कीमतों में तेज वृद्धि धीमी हो गई और केंद्रीय बैंक के स्वीकार्य स्तर पर आ गई संभवतः, यह नयी अर्थव्यवस्था की शुरूआत है। अर्थस्त्री सुराग खोजने के लिए डेटा और अमेरिकी उपभोक्ताओं के व्यवहार से जूँझ रहे हैं। यह महामारी और उसके बाद के दौर में हो सकता है। उपभोक्ताओं के हाथों में अप्रयुक्त धन के बड़े पूल ने अर्थव्यवस्था को चालू रखने में भूमिका निभायी। इस घटना को नियमित रूप से स्वीकार करना बहुत जाखिम भरा हो सकता है।

